

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-117/2005

- 1- हनुमानसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी बनगोठडी कंला  
2- चैनसिंह उर्फ चतरसिंह पुत्र भूरसिंह तहसील चिडावा जिला हुन्डुनू ।
- अपीलान्टस्---

---बनाम---

- 1- रतनसिंह पुत्र डालूसिंह जाति राजपूत  
2- रणाजीतसिंह पुत्र डालूसिंह जाति राजपूत निवासी बनगोठडी  
3- बगडावतसिंह पुत्र डालूसिंह कंला तहसील चिडावा जिला  
4- रणावीरसिंह उर्फ रघुवीरसिंह पुत्र डालूसिंह हुन्डुनू राज0  
5- राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चिडावा जिला हुन्डुनू ।

---रेस्पोंडेन्टस्---

अपील विरुद्ध निर्णय एवं डिक्ली  
दिनांक 25-11-2005 द्वारा  
उप खण्ड अधिकारी चिडावा ।

---0---

उपस्थिति-

- 1- श्री विजयपाल एडवोकेट- अपीलान्ट  
2- श्री हजारीलाल सूनिया एडवोकेट- रेस्पोंडेन्ट

निर्णय दिनांक- 29.12.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 ने अदालत मातहत में दावा बाबत घोषणार्थ बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 141 से 145, 147, 172, 181, 591/141, 592/192 कुल कित्ता-10 रकबा 9.13 हैक्टर ग्राम बनगोठडी कंला वादी एवं प्रतिवादी सं0-1 से 3 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काबत की 8 भूमि है जिसमें प्रत्येक का 1/4, 1/4 एक हिस्सा है जिसका विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है ।

केवल सुविधा के अनुसार ही मौके पर कार्रत करते आ रहे हैं । उक्त आराजी पैत्रिक है जो उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है । वादी अक्सर बीमार रहता है जिसके कारण प्रतिवादी सं०-१ से ५ वादी की १/४ हिस्से की आराजी को हड़पना चाहते है । जिसके चलते दिनांक २५-७-२००३ को वादी को ख०नं० १४३ रकबा ०.८० हैक्टर, ख०नं० १४४ रकबा ०.७३ हैक्टर, ख०नं० १४५ की ०.५६ हैक्टर, ख०नं० १४७ के उत्तरी हिस्से की ०.२० हैक्टर भूमि पर कार्रत करने से मना कियत तथा कार्रत करने पर जान से मारने की धमकी दी । जिस पर यह दावा पेश किया गया । जिस पर अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादी का दावा स्वीकार कर तहसीलदार चिडावा को वादी एवं प्रतिवादी सं०-१ से ३ को उक्त आराजी के १/४, १/४ हिस्से का भौतिक बंटवारा कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाये जाने का आदेश दिया । इस आदेश से धुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने तनकी संख्या-१ का निर्णय रैस्पोंडेन्ट संख्या-१ के पक्ष में कर कानूनी भूल की है । आराजी ख०नं० १४४, १४५ के बाबत रैस्पोंडेन्ट संख्या-१ को खातेदार मानने में कानूनी भूल की है । रैस्पोंडेन्ट संख्या-१ ने ख०नं० १४४ व १४५ पर अपीलान्ट का कब्जा माना है । उक्त कानूनन बिना कब्जे के घोषणा का अनुतोष नहीं दिया जा सकता । रैस्पोंडेन्ट संख्या-२ से ४ की ओर से कोई दावा पेश नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में तनकी संख्या-१ का निर्णय रैस्पोंडेन्ट सं०-१ के पक्ष में करने में कानूनी भूल की है । अदालत मातहत ने साक्ष्य का अवलोकन किये बिना अपना निर्णय पारित किया है । साथ ही तनकी संख्या-१ व ३ का निर्णय एक साथ करने में कानूनी भूल की है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि बिना कब्जे के स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता । रैस्पोंडेन्ट सं०-१ ने अपनी जिरह में ख०नं० १४४ व १४५ पर अपीलान्ट का कब्जा स्वीकार किया है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अपीलान्ट ने भी अपनी साक्ष्य में ख०नं० १४४ व १४५ पर अपना कब्जा साबित किया है जिसका खण्डन रैस्पोंडेन्ट संख्या-१ द्वारा नहीं किया गया है ।

अदालत मातहत ने मौखिक साक्ष्य का अवलोकन न कर अपना निर्णय पारित किया है । साथ ही वादी/रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 का दावा मियाद के बाहर पेशा किया है जिसमें स्थायी निषेधाज्ञा के लिये मियाद 3 वर्ष है । रेस्पोंडेन्ट की ओर से बेदखली की सिद्धि भी नहीं चाही है । इस प्रकार अदालत मातहत ने साक्ष्य का सही रूप से अवलोकन किये बिना तनकीयों का निर्णय संयुक्त रूप से पारित कर कानूनी भूल की है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोंडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

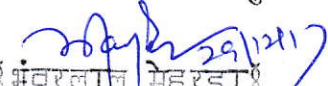
बहस बगौर समाप्त की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं०-2056 से 2059 में ख०नं० 141 से 145, 147, 172, 181, 591/141, 592/192 कुल कित्ता-10 रकबा 9-13 हैक्टर की खातेदारी डालूसिंह पि० रामनाथ के नाम दर्ज है । प्रदर्श-1 मिलान क्षेत्रफल एवं प्रदर्श-पी-6 नक्शा का अवलोकन किया गया । प्रदर्श-2 जमाबन्दी सं०-2027 से 2030 में ख०नं० 95 व 129 कुल कित्ता-2 रकबा 28 बीघा 15 बिस्वा की खातेदारी डालूसिंह पि० रामनाथसिंह के नाम दर्ज है । ख०नं० 53, 59, 94, 131 कुल कित्ता-4 रकबा 56 बीघा 12 बिस्वा में 1/3 हिस्सा की खातेदारी डालूसिंह पि० रामनाथसिंह तथा ख०नं० 116 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा की 2/9 हिस्सा रिभालसिंह, डालूसिंह पि० रामनाथसिंह की खातेदारी में दर्ज है । प्रदर्श-3 में विवादित आराजी डालूसिंह पि० रामनाथसिंह के नाम दर्ज है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है विवादित आराजी पैत्रिक भूमि है जो अभी राजस्व रेकार्ड में रेस्पोंडेन्ट सं०-1 से 4 के पिता की खातेदारी में ही दर्ज है । रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 से 4 डालूसिंह के पुत्र है जिसका कोई विवाद नहीं है । इस आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा हो ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं । रेस्पोंडेन्ट संख्या-1/वादी ने विवादित आराजी में अपने हिस्से की घोषणा के साथ बंटवारा की सहायता एवं



स्थाई निर्बंधान्ना का पेशा किया गया है । राजस्व रेकार्ड में स्पष्टतया विवादित आराजी डालूसिंह की खातेदारी में दर्ज है जिसके चार पुत्र रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 से 4 है जिसका कोई विवाद नहीं है । जिसमें उक्त डालूसिंह के चारों पुत्रों का विवादित आराजी में डालूसिंह के हिस्से में प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा बनता है । जिसकी घोषणा की जाकर अदालत मातहत ने तहसीलदार को मौके के विभाजन प्रस्ताव भिजवाये जाने के आदेश दिये है । अदालत मातहत का यह आदेश तनकीवार्डन विधि पूर्ण है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और संयुक्त कब्जा काल की आराजी में प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जावेगा चाहे उसका कब्जा है अथवा नहीं यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है । अदालत मातहत ने अपना निर्णय विधिनुसार उचित एवं विधिक दिया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी चिडावा का निर्णय एवं डिक्री दि० 25-11-05 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 29.12.2017 को सुनाया गया ।

  
§ भंवरलाल मेहरडा §  
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी  
सीकर